AAE –1 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

नवम्बर, 2009

सार लेखन और मसौदा

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

टिप्पणियां :

(1) सार और प्रारूप तैयार करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करते समय परीक्षार्थी द्वारा उन्हें समझने और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे छोटे वाक्यों में व्यक्त करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गद्यांश को चयनित रूप में दोहरा दे।

(2) इस प्रश्न पत्र में **7** प्रश्न और **4** पृष्ठ हैं।

(3) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लिखिए और उसे उपयुक्त शीर्षक दीजिए:-

ग्रामीण भारत में 700 मिलियन से अधिक लोग हैं जो पारिस्थितिकी रूप से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लगभग 1.42 मिलियन निवास स्थानों पर रहते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करना अत्यंत भीषण कार्य है विशेष रूप से जबकि उनकी जागरूकता, सामाजिक - आर्थिक विकास, शिक्षा, गरीबी, परम्परा और रीति-रिवाज तथा पानी की उपलब्धता के स्तर में समानता न हो।

ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने 2005 में भारत निर्माण की शुरूआत की है जिसे पांच वर्ष की अवधि में लागू किया जाना है। ग्रामीण पेय जल भारत निर्माण के छह संघटकों में से एक है। भारत निर्माण अवधि के दौरान शामिल न किए गए 55067 और उपेक्षित लगभग 3.3 लाख निवास स्थानों को पेय जल सुविधाओं से युक्त किया जाना है और 2.17 लाख गुणवत्ता से रहित निवास स्थानों की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को दूर किया जाना है। गांव/निवास स्थान के स्तर पर पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल के संयुक्त उपयोग अर्थात वर्षा के जल, जमीन की सतह पर उपलब्ध जल और भू-जल के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रणाली को बनाए रखने के लिए पेय जल पूर्ति विभाग ने

ग्रामीण पेय जल आधारभूत संरचना को चालू रखने और उसका रख-रखाव करने में समाज की भागीदारी को संस्था का रूप प्रदान करने के लिए व्यापक प्रयास किया है। कम लागत की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा न केवल पेय जल की आवश्यकता को पूरा करने बल्कि जल के पुनर्भरण के लिए भी दिया जा रहा है। जल विभाजक विकास और प्रबंधन के कार्य में सभी विभागों के प्रयासों का अभिमुखीकरण जल आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी लम्बे समय तक जारी रहेगा। यह देखा गया है कि भू-जल के गिरते स्तर के कारण कुछ क्षेत्रों में अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक और खारेपन की अधिकता से गुणवत्ता की समस्या बढ़ गई है।

जमीन से जितना जल निकाला जाता है उसका 85% सिंचाई के काम आता है। जमीन से निकाला जाने वाला शेष 15% जल उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कई राज्यों में जमीन के पानी से सिंचाई का तेजी से विकास किए जाने के परिणामस्वरूप भू-जल स्तर में गिरावट आई है। इससे पेय जल आपूर्ति के स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भू-जल के विकास को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक नमूना विधेयक सभी राज्य सरकारों को उनकी संबंधित राज्य विधान सभाओं में अधिनियम बनाने के लिए परिचालित किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे शहरी निर्माणों के लिए वर्षा के जल को एकत्र करने की संरचना बनाना अनिवार्य कर दें। केंद्र सरकार ने 2008 में एक स्कीम की घोषणा की थी जिसमें किसानों के लाभ के लिए पहचान किए गए राज्यों के 110 ब्लाकों में भू-जल के पुनर्भरण के लिए 4455 मिलियन कुओं का उपयोग किया जाएगा। देश में भू-जल संसाधनों का अधिक दोहन किए जाने से उत्पन्न चिंता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए रखे जाने योग्य जल संसाधन प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कुओं के माध्यम से भू-जल के कृत्रिम रूप से पुनर्भरण का कार्य शुरु किया गया है। जिन क्षेत्रों में भू-जल का अधिक उपयोग किया जाता है उनमें से लगभग 80% का अधिक दोहन किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु जहां दीर्घ अवधि आधार पर भू-जल का तेजी से गिरता स्तर देखा गया है, राज्यों के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में स्थित संकटपूर्ण और अर्ध संकटपूर्ण स्थानों का पता लगाया गया है। इस स्कीम को पंचायती राज संस्थाओं, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना है। जिस किसान ने पहचान किए गए क्षेत्र में अपनी कृषि भूमि में कुआं खोदा है वह इस स्कीम का लाभ उठा सकेगा।

ग्रामीण समाज, ग्राम स्तर पर जल पूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी मिलजुल कर उठा सके इसके लिए स्वजल धारा के रूप में विकेन्द्रीकृत, मांग आधारित और समाज द्वारा प्रबंधित व्यवस्था अपनाई गई है। पेय जल के क्षेत्र में जल को बनाए रखने के लिए समाज की भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फरवरी, 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण का कार्य शुरु किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेय जल स्रोतों का नियमित रूप से सर्वेक्षण करने के लिए 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए जल परीक्षण किटों सहित 100% सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण का उद्देश्य है जल की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना करके एकीकृत प्रणाली का विकास करना, सूचना देना और ग्रामीण जनसमुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना।

(25 अंक)

2. **उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए।**

   (क) जल संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी विभागों का उल्लेख कीजिए।

   (ख) वर्षा जल का संरक्षण, भू-जल स्तर के सुधार में किस प्रकार सहायक हो सकता है?

   (ग) जल संकट को दूर करने के लिए तीन उपाय सुझाइए।

(15 अंक)

3. **केंद्रीय योजना निगरानी परियोजना साफ्टवेयर के लाभ बताते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर अपने मंत्रालयों में लागू किए जाने के लिए महालेखा नियंत्रक की ओर से सभी सचिवों को भेजे जाने वाले अर्ध शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए।**

(20 अंक)

4. **"सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता सुनिश्चित करने का साधन है" - इस पर टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों के भीतर)** *(25 अंक)*

5. निम्नलिखित शब्दों के तीन-तीन पर्याय लिखिए:-

1. बर्फ
2. नौका
3. सवेरा
4. धनुष
5. युद्ध *(5 अंक)*

6. वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए -

1. जो सहन न कर सके
2. छिपाने योग्य
3. गोद लिया हुआ पुत्र
4. खोज करने वाला
5. वर्षा न होना । *(5 अंक)*

7. निम्नलिखित के हिन्दी शब्द लिखिए -

i) Demand for Grants
ii) Explanatory Notes
iii) Primary Deficit
iv) Expenditure Budget
v) Annual Financial Statement

(5 अंक)

AAE – 1 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

NOVEMBER, 2009

PRECIS AND DRAFT

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

Note : 1. While evaluating the question on precis and drafting the candidates would be evaluated for their understanding and ability to express the same in short sentences using simple words. He would not be expected to reproduce the passage selectively.

2. This question paper contains **7** questions and **4** pages.

3. All the questions are **compulsory**.

1. Write a précis of the following passage and give a suitable title:

Rural India has more than 700 million people residing in about 1.42 million habitations spread over diverse ecological regions. Meeting drinking water needs of such a large population can be a daunting task especially with non uniformity in level of awareness, socio-economic development, education, poverty, practices and rituals and water availability.

To build rural infrastructure, Bharat Nirman has been launched by Government of India in 2005 to be implemented in a period of five years. Rural drinking water is one of the six components of Bharat Nirman. During the Bharat Nirman period 55067 uncovered and about 3.3 lakh slipped back habitations are to be covered with provision of drinking water facilities and 2.17 lakh quality affected habitations are to be addressed for quality problem. To achieve drinking water security at village/habitation level, conjunctive use of water i.e. judicious use of rain water, surface water and ground water is promoted. For sustainability of system, Department of Drinking Water Supply has undertaken extensive exercise for institutionalization of community

participation in operationalisation and maintenance of rural drinking water infra structure. Low cost technologies are being promoted not only for meeting drinking water requirement but also for recharging of the water table. Convergence of efforts of all Departments in water shed development and management would go a long way in meeting water needs. It has been noticed that ground water depletion has aggravated water quality problems due to excess fluoride, arsenic and brackishness in certain areas.

Irrigation accounts for 85% of all ground water extraction. The remaining 15% of the ground water extraction is utilized by other sectors including industries. The rapid development of ground water based irrigation in many states has caused ground water depletion. This affects the drinking water supply source adversely. A model bill to regulate and control the development of ground water, drafted by Ministry of Water Resources, has been circulated to all the State Governments for enactment by their respective state legislative assemblies. Ministry of Urban Development has been requested to make rainwater harvesting structure mandatory for urban constructions. The Central Government announced a scheme in 2008 in which 4455 million wells will be taken up for recharging ground water in 110 blocks of the identified states for the benefit of farmers. The artificial recharge of ground water through wells has been launched keeping in view of the concerns of over exploitation of ground water resources in the country as well as to ensure sustainable water resource management and irrigation facilities in the affected rural areas. About 80% of these ground water stressed areas are over exploited. Critical and semi critical areas are located in hard rock areas in the states of Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu where rapid decline of ground water levels has been observed on long term basis. The scheme is to be implemented by the respective state government in association with Panchayati Raj Institutions, the Central Ground Water Board, the NABARD and NGOs. The farmer who has dug well in his agricultural land in the identified areas is the beneficiary for the scheme.

To enable the rural community shoulder the responsibility in management, operation and maintenance of water supply systems at village level, decentralized, demand driven, and community – managed approach in the

form of Swajal Dhara have been adopted. To further strengthen community participation in the drinking water sector for sustainability, national rural drinking water quality monitoring and surveillance has been launched in Feb' 2006 under which 5 persons in each Gram Panchayat are to be trained to carry out regular surveillance of drinking water sources for which 100% assistance including water testing kits are provided. The objective of the WQM&S is to develop an integrated system by setting up of district level labs for water quality testing, reporting and generating awareness in rural masses. *(25 marks)*

2. **Answer the following questions based on the passage above. The answer should be in approximately 50 words each.**
   (a) Mention the Departments responsible for management of water problems.
   (b) How rainwater harvesting can help to improve ground water table?
   (c) Suggest three measures to overcome water crisis. *(15 marks)*

3. **Draft a DO letter from CGA to all Secretaries to implement Central Plan Monitoring Project Software (CPMPS) in their Ministries on priority highlighting its benefits.** *(20 marks)*

4. **"Right to Information Act is a tool to ensure transparency" – comment on it (in not more than 150 words)?** *(25 marks)*

5. **Change the following sentences into indirect speech:**
   (i) The clerk said to the manager, "Please, do not refuse leave to me."
   (ii) "Is the train late?" The man said to the station master.
   (iii) She said, "They have already published the results."
   (iv) "What do you want?" He said to me.
   (v) "What time the mail arrives in the village?" The woman asked.

   (5 marks)

6. (a) **Make sentences indicating the meaning of the following phrases –**

(i) Fall out

(ii) Make off

(iii) Carry out

(b) Change the following into passive voice -

(i) I shall not speak a word to you.

(ii) Do not raise the objection. *(5 marks)*

7. **Complete the following sentences with suitable prepositions.**

(a) The water was flowing _____ the danger level.

(b) He is indebted _____ his friend _____ a large sum.

(c) She is ignorant_____what he pretends to know.

(d) His income is not adequate.....his wants.

(e) The accident resulted.....the death of 5 people.

(5 marks)